



T M

नगर संस्करण

C
M
Y

आधुनिक भारत का आधुनिक नजरिया

आधुनिक समाचार

हिन्दी साप्ताहिक

12



18/11/2024



19/11/2024



20/11/2024



NAINI INDUSTRIAL TRAINING CENTRE

(Govt. Affiliated, Star Graded, Record Holder, ISO Certified Training Centre)

सर्टिफिकेट इन फायर सेफ्टी एण्ड हॉपडस्ट्रीयल सिक्योरिटी

फायर सेफ्टी पर जिसकी कमाण्ड, उसकी ही है ग्लोबल डिमाण्ड
कोर्स के बाद सेफ्टी सुपरवाइजर, फायर प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर
आदि विभिन्न पदों पर नियुक्ति मिल जाती है। रिलीफ एजेन्सी N.G.O.,
डिफेंस सर्विसेज फायर सर्विस आईनिंज्स फैक्ट्री, महानगर पालिका, नगर
निगम, एयरपोर्ट, पावर प्लांट, स्टील प्लान्ट, माइनिंग हॉल्डस्ट्रीज, पेट्रोलियम
कम्पनी, फूड हॉपडस्ट्रीज, रिफाइनरीज, टेक्सस्टाइल मिल, टावर कम्पनी,
इलेक्ट्रॉनिक कम्पनी, कोयले की खदानों एवं जहाजों आदि क्षेत्रों में फायर
सेफ्टी के जानकारी को बहुत अधिक मौका मिलता है

नोट: फायर सेफ्टी कोर्स करें और देश -विदेश, सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों में अच्छे पैकेज के साथ नौकरी पायें।

Visit us at www.nainiiti.com Call: 9415608710, 7459860480



21/11/2024



22/11/2024



23/11/2024

सम्पादकीय

एएमयू पर एक और
फैसले की प्रतीक्षा,
एससी-एसटी और
ओबीसी आरक्षण क्यों
नहीं होना चाहिए

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एमयू) पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का निहितार्थ क्या है? शीर्ष अदालत की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने 1967 के फैसले को 4-3 से पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि यह अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं है। यह स्थापित सत्य है और स्वयं एमयू की आधिकारिक वेबसाइट में इसका उल्लेख है कि यह विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खान का विचारबीज है। 17 अक्टूबर 1817 को जन्मे सर सैयद अहमद खान 1838 में इस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों की सहायता की। उनका विश्वास जीतकर वह 1867-76 के बीच ब्रिटानी अदालत में न्यायाधीश रहे। अप्रैल 1869 में सर सैयद को इंग्लैंड में 'आईर आफ द स्टर आफ इंडिया' से नवाजा गया, तो 1887 में लाई डफरिन ने उन्हें 'सिविल सेवा आयोग' का सदस्य बना दिया। 'खान बहादुर' नाम से प्रख्यात सर सैयद की वफादारी से प्रमुदित ब्रिटिश हुक्मत ने उन्हें 1898 में 'नाइट' की उपाधि दी। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना के साथ देश में पूर्ण स्वतंत्रता और लोकतंत्रीय व्यवस्था की मांग उठी शुरू हुई, तब ब्रिटानियों के प्रति निष्ठावान सर सैयद ने मुस्लिमों को राजीय अंदोलन से दूर करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने 'हिंदू-मुस्लिम', 'हिंदी-उर्दू', 'संस्कृत-फारसी' का मुद्दा उठाकर मुसलमानों की मजहबी भावनाओं के जरिये विचार स्थापित किया कि मुसलमान का कर्तव्य है कि वह अंग्रेजों के निकट और कांग्रेस से दूर रहे। इस अभियान में वह काफी हद तक सफल भी हुए, क्योंकि मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा को संबोधित करते हुए लियाकत अली खान (पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री) ने कहा, ठहम मुस्लिम राष्ट्र की स्वतंत्रता की लड़ाई जीतने के लिए आपको उपयोगी गोला-बारूद के रूप में देख रखे हैं। ठब कालांतर में हुए चुनावों में एमयू छात्रों-शिक्षकों ने बढ़-चढ़कर मुस्लिम लीग का समर्थन किया। जो मुस्लिम नेता (मौलाना आजाद और प्रो हमायून कबीर आदि) तब विभाजन का विरोध कर रहे थे, उन पर एमयू छात्रों ने मजहब का शत्रु मानते हुए हमला किया। विभाजन और स्वाधीनता पश्चात अपेक्षा थी कि या तो एमयू बंद होगा या फिर इसके आधारभूत चिंतन में परिवर्तन आएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला किया। इसके एक दिन पहले तक एमयू छात्र पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो रहे थे। इसकी भनक लगते ही उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बलभूषण ने गृहमंत्री सरदार पटेल को चिन्ही लिखी और विश्वविद्यालय में पाकिस्तानी सेन्य अधिकारियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया। मई 1953 को विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति जाकिर हुसैन ने नेहरू सरकार को जानकारी दी कि कई पाकिस्तानी एमयू में दाखिला ले रहे हैं। अगस्त 1956 में एमयू छात्रों ने 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए। इसी विश्वविद्यालय में अलगावादी तत्त्वों के बढ़ते प्रभाव के बीच जाकिर हुसैन ने कुलपति पद से इस्तीफा दे दिया। जब 1965 में नवाब अली यावर जंग को एमयू का अगला कुलपति नियुक्त किया गया, तब छात्रों ने उन पर घातक हमला कर दिया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें लींगी। एमयू 2018 में



भी अपने 'जिज्ञा प्रेम' के कारण विवादों में था। स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं (स्वाधीनता सहित) और एम्यू के घोषित होड़े के बीच टकराव था। जब शेष भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत था, तब एम्यू सर सेयर्ड के 'दो-राष्ट्र' सिद्धांत को मूर्त रूप दे रहा था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में एक अलग इस्लामी देश- पाकिस्तान को जन्म दिया। एम्यू के इस चरित्र से स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पं. नेहरू भी परिचित थे। 24 जनवरी, 1948 को एम्यू के दीक्षांत समारोह में भाषण देते हुए नेहरू ने कहा था, मुझे अपनी विरासत और अपने पैरों पर गर्व है, जिन्होंने भारत को बीड़क और सांस्कृतिक श्रेष्ठता प्रदान की। आप इस अतीत पर कैसा अनुभव करते हैं। हमारे मजहब अलग-अलग हो सकते हैं, किंतु यह उस सांस्कृतिक विरासत से वंचित होने का कारण नहीं बन जाता, जो आपकी भी है और मेरी भी। आजादी के बाद स्वतंत्र भारत ने हाशिये पर पढ़े जानकार जेन वर्गों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा, जिन्होंने ऐतिहासिक अन्याय छोला था। इसके परिमार्जन के लिए सकारात्मक और दृढ़ कदम उठाते हुए संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। कांग्रेस सहित स्वयंभू सेक्युलरवादियों की अनुकंपा से एम्यू लगातार समाज के इन दोनों वर्गों समेत ओबीसी को भी संवैधानिक अधिकार देने से इन्कार करता रहा। यक्ष प्रश्न यह है कि क्या स्वतंत्र भारत में सरकार द्वारा वित्तपैषिण संस्थान में एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? यह वह प्रश्न है, जिस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए? देखना है।

सुनिश्चित की जाए बच्चों की सुरक्षा, आखिर वे पढ़ेंगे कैसे

बहुत पुरानी बात नहीं इसी साल जनवरी में ह्यू बताया गया था कि बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम में 32 प्रतिशत की बढ़ोतारी हुई है। अफसोस की बात यह है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। वैसे तो बच्चे और बचियां दोनों ही यौन अपराधों का विकल्प होते हैं।

तो यौन अपराध को समझ भी नहीं सकती। उनके दिल में ऐसी घटनाओं के प्रति इतना भय बैठ जाता है कि कई बार उसे दूर करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पुलिस उन बचियों की काउंसिलिंग करती है, जिनके साथ ऐसा अपराध हुआ होता है। चिंता की बात यह है कि ऐसी खबरें लगातार किया गया। इन सभी मामलों में बच्चों के माता-पिता स्कूल में विरोध करने भारी संख्या में पहुंचे। एनसीआरबी के 2023 के आंकड़ों के अनुसार 2022 में बच्चों के प्रति अपराधों (यौन अपराध समेत) में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दिल्ली में सबसे अधिक 7,400, मुंबई में 3,178, बैंगलुरु में 1,578

यह है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। वैसे तो बच्चे और बच्चियां दोनों ही योन अपराधों का शिकार हो रहे हैं, मगर बच्चियों की संख्या ज्यादा है। सवाल यह है कि जिन स्कूलों में बच्चे और बच्चियां पढ़ने जाते हैं, वहाँ जब कोई अपराध हो जाता है, तभी अधिकारी जब ऐसे सर्वेक्षण किए जाते थे कि माता-पिता अधिकर अपनी बच्चियों को स्कूल क्यों नहीं भेजते या बीच में ही उनकी पढ़ाई क्यों छुड़ाव दी जाती है तो माता-पिता यही कहते थे कि उन्हें अपनी लड़कियों की सुरक्षा की चिंता रहती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब स्कूल जाने वाली की चिंता भी उतनी नहीं रहती थी, लेकिन जब दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में स्कूलों में बच्चियों-बच्चों के प्रति तरह-तरह के अपराध हो रहे हैं, तो क्या यह धारणा गलत मान ली जाए कि महानगर महिलाओं, बच्चियों, लड़कियों के लिए अधिक सुरक्षित होते हैं?

रचनात्मक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करता भारत, नवरचना को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

क्रिएट इन इंडिया चैलेंज भारत की सृजनात्मक अर्थव्यवस्था (क्रिएटर इकोनामी) की अपार संभावनाओं को उत्तम करने के लिए डिजाइन की गई एक अप्रयुक्ति पहल है। वेस की तैयारी के हिस्से के रूप में शरू की गई इन चुनौतियों का उद्देश्य एनैमेशन गमिंग संगीत और एंटीटी कंटेंट और इमर्सिव स्टोरीलेटिंग जैसे प्रमुख छेत्रों परिवृद्धि की जीवंतता को दर्शाता है। 3,375 करोड़ रुपये मूल्य वाले एक प्रभावशाली मार्कीटिंग क्षेत्र और 2,00,000 से अधिक पूर्णकालिक सामग्री निर्माताओं के साथ यह उद्योग भारत की वैश्विक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने वाली एक गतिशील शक्ति है। गुणाहाटी, कोच्चि और इंदौर आदि शहर रचनात्मक केंद्र बन रहे हैं, जो

भागीदारों को अपने से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज भारत की सुजनातमक अर्थव्यवस्था (क्रिएटर इकोनॉमी) की अपार संभावनाओं को उजागर करने के लिए डिजाइन की गई एक अग्रणी पहल है। वेट्स की तैयारी के हिस्से के रूप में शुरू की गई इन चुनौतियों का उद्देश्य एनिमेशन, गेमिंग, संगीत,

सत्ता के लिए सब कुछ दांव
पर, नीति-सिद्धांत-

महाराष्ट्र और झारखण्ड विधानसभा चुनावों में जोड़तोड़-गठजोड़ से लेकर लोक लुभावन वायदों तक पर जोर बताता है कि सत्ता के दावेदारों को अपने दम पर भरोसा नहीं। ये दावेदार कभी-न-कभी सत्ता में रह चुके हैं। फिर ऐसा क्यों है कि उन्हें अपने काम पर जनादेश का विश्वास नहीं? इस सवाल का जवाब बिना दिए भी समझा जा सकता है। इसीलिए दोनों ही राज्यों में येन केन प्रकारण सत्ता हासिल करने के लिए जोड़तोड़-गठजोड़ से लेकर मुफ्त की रेविडियों तक हरसंभव बिसात बिछानी पड़ी

में नीति-सिद्धांत विचारधारा न इधर थी, न उधर। बस सत्ता की धारा ही सभी के सिर चढ़ कर बोल रही थी। जब जैसे जिसको मौका मिल रहा था, वह सत्ता की धारा में डूबकी लगा रहा था। महाराष्ट्र में परिवार भी ढूटे। अब अजित पवार ने कहा है कि 2019 के नाटक के रचयिता तो शरद पवार ही थे। मान चाचा ने भी लिया है कि हाँ, वह भाजपा के साथ सरकार बनाने की विचार प्रक्रिया में शामिल थे, पर उस पर भरोसा नहीं कर पाए। महाराष्ट्र के चुनावी परिदृश्य में भाजपा और कांग्रेस ही



में प्रतिभाओं को प्रेरित और सशक्त बनाना है। आप पूरी दुनिया में भारत के डिजिटल प्रतिनिधि हैं। आप वोकल फार लोकल के ब्रांड एंबेसडर हैं। इस साल के शुरू में प्रधानमंत्री नरन्द्र मोदी द्वारा प्रथम नेशनल क्रिएटर अवार्ड प्रदान करते समय कहे गए थे प्रेरक शब्द भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था की परिवर्णनकारी भूमिका को उजागर करते हैं। आज हमारे रचनाकार केवल कहानीकार नहीं हैं, वे राष्ट्र का निर्माण कर भारत की पहचान को आकार दे रहे हैं और वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र की गतिशीलता का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज से गोवा में 55वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आइएफएफआइ) का आरंभ हो रहा है, जिसकी थीम 'युगा फिल्म निर्माता-भविष्य अब है।' अगले आठ दिनों में आइएफएफआई सैकड़ों फिल्मों के प्रदर्शन के साथ फिल्म क्षेत्र के दिग्गजों के साथ संवाद करेगा। इसमें वैश्विक सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। वैश्विक और भारतीय सिनेमाई उत्कृष्टता का यह संगम भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को नवाचार, रोजगार और सांस्कृतिक कृतीनीति के एक केंद्र के रूप में व्यक्त करता है। भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था 30 बिलियन डॉलर के उद्योग के रूप में सामने आई है, जो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2.5 प्रतिशत का योगदान देती है और 8 प्रतिशत कार्यवल को रोजगार प्रदान करती है। सिनेमा, गेमिंग, एनीमेशन, संगीत, प्रभातशाली मार्केटिंग और अन्य गतिविधियों को समाहित करने वाला यह क्षेत्र भारत के सांस्कृतिक विकेंद्रीकृत रचनात्मक क्रति को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत के 110 करोड़ सौशल मीडिया उपयोगकर्ता और 70 करोड़ सौशल मीडिया उपयोगकर्ता रचनात्मकता के इस लोकतंत्रीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। सौशल मीडिया प्लेटफार्म और ऑटोटीटी सेवाएं रचनाकारों को विश्व स्तर पर दर्शकों से सीधे जुड़ने में सक्षम बनाती हैं। क्षेत्रीय सामग्री और स्थानीय स्तर की कहानी की प्रतिभा ने कथा को और विविधता प्रदान की है, जिससे भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था वास्तव में समावेशी बन गई है। ये सभी कंटेंट क्रिएटर अर्थिक स्तर पर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इनके दस लाख से ज्यादा कालोअर्स हैं और ये प्रति माह 20,000 से 2.5 लाख रुपये तक कमा रहे हैं। यह व्यवस्था अर्थिक रूप से लाभकारी है और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और सामाजिक प्रभाव के लिए एक मंच भी। रचनात्मक अर्थव्यवस्था का गहरा प्रभाव है, जो सकल घरेलू उत्पाद के विकास से कहीं आगे तक विस्तारित है। यह पर्यटन, आतिथ्य और वैश्विक सिंहित विभिन्न क्षेत्रों के सहायक उद्योगों को काफी प्रभावित करता है। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफार्म उपक्षित लोगों की आवाज भी मजबूती से उठाता है। यह सामाजिक समावेशन, विविधता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को भी समुद्र करता है। कथय प्रस्तुत करने की अपनी कला द्वारा भारत ने बालीवुड से लेकर क्षेत्रीय सिनेमा तक अपनी वैश्विक साप्ट पावर को मजबूती दी है, जो विश्व मंच पर प्रचुर सांस्कृतिक भाव प्रदर्शित करता है।

ओटीटी कंटेंट और इमर्जिंग स्टोरीटेलिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिभाओं को प्रेरित और सशक्त बनाना है। 14,000 से अधिक पंजीकरणों और स्टार्टअप्स, स्वतंत्र रचनाकारों और उद्योग के पेशवरों की सक्रिय भागीदारी के साथ यह पहल भारत की अभिनव भावना को प्रदर्शित करती है। जब हम आइएफएफआईमें सिनेमाई प्रतिभाके इस आठ दिवसीय उत्सव की शुरुआत कर रहे हैं, तो संदेश स्पष्ट हैः भारत के रचनाकार वैश्विक रचनात्मक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार नीतिगत सुधारों, बुनियादी ढाँचे के विकास और नवाचार के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से इसके क्षेत्रों का समर्पण करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारे रचनाकारों के लिए कार्रवाई का आहान सरल, लेकिन गहरा है। वे 53, वर्तुअल प्रोडक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिंजेंस जैसी अन्याधुनिक तकनीक अपनाएं तथा ऐसे प्लॉफार्म का लाभ उठाएं, जो भौगोलिक बाधाओं को पार करते हैं और ऐसी कहानियां बताते हैं, जो भारत की अनूठी पहचान दर्शाते हुए वैश्विक स्तर पर गूंजती हैं। भविष्य उन लोगों का है जो नवाचार करते हैं, सहयोग करते हैं और सहजता से सूजन करते हैं। आइए हम साथ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हर भारतीय रचनाकार एक वैश्विक कहानीकार बने, ताकि भविष्य को आकार देने वाली कहानियों के लिए पूरा विश्व भारत की ओर देखे।

है। सत्ता के इस खेल में इस बात की परवाह किसी ने नहीं की कि इन राज्यों की पहले से खराब अर्थव्यवस्था के लिए उनकी चुनावी चालें कितनी घातक साबित होंगी। दरअसल सत्ता की जंग में सब कुछ जायज मान लिया गया है—और इस काम में कोई किसी से पीछे नहीं। पिछले पांच साल महाराष्ट्र लगातार राष्ट्रीय राजनीति के भी केंद्र में बना रहा। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा-शिवसेना को मिले स्पष्ट बहुमत से लेकर मुख्यमंत्री पद पर टकराव और अलगाव तथा फिर बेमेल गठबंधनों की बीच सत्ता के खेल तक महाराष्ट्र ने राजनीतिक पतन के नए अमावस्या ही स्थापित किए। भाजपा ने शरद पवार की राकांपा से भीतीजे अजित पवार की कुछ दिनों की बगावत के जरिये 80 घटों की सरकार बना कर अपनी साख दांव पर लगाई तो मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्घव ठाकरे ने उसी कांग्रेस से हाथ मिला लिया, जिसके विरुद्ध उनके पिता बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी। राजनीति की नाटकीयता यहीं समाप्त नहीं हुई। हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने सबसे पुराने और मुखर साथी रहे बाला साहेब के उत्तराधिकारी उद्घव को मुख्यमंत्री न बनाने वाली भाजपा ने उनकी शिवसेना तोड़ने वाले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और अपने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना कर अपनी साख फिर सवालिया निशान स्वर्यं लगा लिया। 80 घटों की फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री रह कर राकांपा में लौट गए अजित में फिर बगावत ने अंगाझी ली और वह विधायकों के बहुमत के साथ पार्टी लोड कर भाजपा-शिंदे शिवसेना की महायुति सरकार संग जाकर पांचवीं बार राज्य के उप मुख्यमंत्री बन गए। सत्ता के इस खेल दो बड़े दल हैं। भाजपा की महायुति और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी, दोनों में ही गिनती के लिए तीन-तीन दल हैं, लेकिन दरअसल शेष दो दल विभाजित गुट हैं, जिनकी राजनीतिक स्त्रीकार्यता की परीक्षा हैं ये चुनाव। शिंदे के नेतृत्ववाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्ववाली राकांपा, महायुति में हैं तो उद्घव के नेतृत्ववाली शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्ववाली राकांपा, महाविकास आघाड़ी में हैं। विचित्र स्थिति है कि दोनों बड़े दल इन गुटों पर ज्यादा निर्भर नजर आ रहे हैं, जबकि उनकी विश्वसनीयता सदियों बनी हुई है। शरद पवार अपने विधायकों की संख्या से भी कई गुणा सीटें अपनी राकांपा के लिए हासिल करने में सफल रहे। अजित पवार महायुति में होते हुए भी भाजपा की चुनावी रणनीति का मुखर विरोध कर रहे हैं। भाजपा जिन नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आरोप लगाती रही, उन्हें और उनकी बेटी को भी अजित ने विधानसभा टिकट दिया। यह कौन-सा गढ़बंधन धर्म है? शिंदे के साथ भाजपा के रिश्ते सहज नज़र आते हैं, पर उन्हें दी गई ज्यादा सीटों में राजनीतिक जोखिम भी है। खुद सत्ता के दावेदारों में ऐसे भ्रम के बीच मतदाता के लिए किसी दल-उम्मीदवारों का चयन आसान तो नहीं होगा। ज्ञारखंड का चुनावी परिदृश्य भी जोड़तोड़ और वायदों के मायाजालों से मुक्त नहीं है। तमाम आशंकाओं के बीच ज्ञारखंड मुक्ति मोर्चा-कांग्रेस राजद गठबंधन सरकार कार्यकाल पूरा करने में सफल रही, लेकिन इस बीच एक 'मनी लांड्रिंग' भामले में मुख्यमंत्री पद छोड़ कर हेमत सोरेन को कुछ महीने जेल में गुजारने पड़े।

